विचार बिन्दु

उत्साह मनुष्य की भाग्यशीलता का पैमाना है। –तिरुवल्लुवर

मांगें राज्य की देने की क्षमता पर भारी पड़ने लगी हैं

भारतीय लोकतंत्र की यात्रा एक प्रकार से जन-आकांक्षाओं और मांगों के विस्तार की यात्रा रही है। आजादी के सात दशकों बाद वह जिस मुकाम पर पहुंच गई है वहां प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति के चलते लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को अनोखे झंझावात से झूंझना पड रहा है। हर तरफ 'राजनीतिकरण' की प्रक्रिया, जो एक दुधारी तलवार की तरह होती है, अपने चरम पर है। एक तरफ, इसने सदियों से हाशिए पर रहे समुदायों, जातियों और वर्गों को आवाज़ दी है, उन्हें संगठित किया है और राजनीतिक व्यवस्था से अपना हक मांगने के लिए तैयार किया है, लेकिन इसी प्रक्रिया का दूसरा पहलू सबके लिये चिंता का विषय है। जब राज्य व्यवस्था पर नई मांगों का बोझ उसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाता है, तो सिस्टम में ओवरलोड की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में राज्य की व्यवस्था आज इसी ओवरलोड को झेल रही है। एक तरफ उम्मीदों और मांगों का कोई छोर नहीं है, तो दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक तंत्र की बोझ उठाने की क्षमता क्षीण है। एक तरफ सशक्तीकरण का उजला पक्ष है तो दूसरी तरफ मांगों की बाढ़। यह जरूर है कि राजनीतिकरण की प्रक्रिया ने लोकतंत्र को जन-आनुपातिक बनाया है। आज भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी इलाके या पृष्ठभूमि से हो, वह अपने वोट की कीमत को समझता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा अब केवल नीतिगत दस्तावेज में लिखे हर्फ़ नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक सौदेबाजी के मुख्य हथियार बन चुके हैं। इस प्रक्रिया ने समाज के विभिन्न समूहों को यह सिखाया है कि कैसे वे जाति, धर्म, क्षेत्र या वर्ग की अपनी पहचान के आधार पर गोलबंद होकर राज्य पर दबाव बना सकते हैं। आरक्षण के लिए नए समुदायों के आंदोलन, किसानों द्वारा अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने की मांग, या युवाओं द्वारा सरकारी नौकरियों में त्वरित भर्ती के लिए किए जाने वाले प्रदर्शन इसी राजनीतिक चेतना के परिणाम हैं। व्यवस्था पर यह दबाव लोकतंत्र के जीवंत होने का प्रमाण है। यह साबित करता है कि जनता अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि नीति-निर्धारण में एक सक्रिय हितधारक है। मगर इनके साथ-साथ हम व्यवस्था पर 'ओवरलोड' और अक्षमता का संकटभी झेल रहे हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इस राजनीतिकरण की गति और मांगों की मात्रा, राज्य की संस्थागत क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा, न्यायिक व्यवस्था और वित्तीय तंत्र आज भी पुरानी औपनिवेशिक विरासत और सीमित संसाधनों के बोझ तले दबे हैं। जब हर समूह अपनी मांगों को लेकर सड़क से संसद तक दबाव बनाता है, तो राज्य के सामने प्राथमिकताओं का संकट खड़ा हो जाता है। इसी सिस्टम ओवरलोड के फलस्वरूप भारतीय राज्य कई मोर्चों पर लगातार नाकाम होता दिखने लगता है। राजनीतिक दल चुनावों को जीतने के लिए लोक-लुभावन वादों और मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं। यह भी राजनीतिकरण का ही एक हिस्सा है, जो जनता को मुफ्त बिजली, पानी या नकद हस्तांतरण की मांग करने के लिए उकसाता है। इसका सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ता है। जब राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन तात्कालिक मांगों को पूरा करने में चला जाता है, तो दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य और उद्योग के लिए पूंजी नहीं बचती। इसी कारण मौजूदा सरकारें उधार लेकर बढ़ते वित्तीय दबाव को झेल रही हैं।

यह भी सच है कि भारतीय नौकरशाही भी जन अपेक्षाओं के इस बोझ को संभालने में अक्षम साबित हो रही है। जब किसी एक मांग को पूरा करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, तो दूसरा समूह उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसे हम भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव के रूप में रोज देखते हैं। इस अंतहीन खींचतान में प्रशासनिक तंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, जिससे विकास की परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहती हैं। नौकरशाही का औपनिवेशिक और सामंती परिवेश भी नहीं बदला है, जिससे भ्रष्टाचार शासन तंत्र की रग-रग में समा चुका है। इसके चलते लोकतान्त्रिक जागरूकता ने न्यायिक और नियामक संस्थाओं पर दबाव जबरदस्त बढ़ा दिया है। जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मांगों का समाधान नहीं होता, तो स्वाभाविक ही लोग न्यायपालिका के पास पहुंचते हैं। भारतीय अदालतों में करोड़ों मुकदमों का लंबित हैं। हमारी न्याय व्यवस्था विवादों को समय पर सुलझाने में नाकाम रही है। अब तो न्यायिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। नियमन करने वाली संस्थाएं भी राजनीतिक दबावों और जन-आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने में असफल होती दिख रही हैं। दुर्भाग्य से पहचान की राजनीति और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण मांगें सार्वभौमिक होने के बजाय विशिष्ट समूहों की बन रही हैं। विकास की मांग अब सबके विकास के रूप में नहीं, बल्कि मेरी जाति या मेरे क्षेत्र के विकास के रूप में की जाती है। प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में निर्वाचित राजनेता भी अब अपने और अपनों के लिये हो रहते हैं। जब राज्य सीमित संसाधनों के कारण सभी मांगों को एक साथ पूरा नहीं कर पाता, तो वह तुष्टिकरण या चयनात्मक समाधान का रास्ता चुनता है। इससे समाज में एक नया असंतोष जन्म लेता है। जो समूह पीछे छूट जाते हैं, वह शासन व्यवस्था को पूर्वाग्रह से ग्रसित मानने लगते हैं। यह स्थिति राज्य की वैधता को कमजोर करती है। जनता का यह भरोसा टूटने लगता है कि राज्य एक निष्पक्ष मध्यस्थ है। जब राज्य सुरक्षा, त्वरित न्याय और समान अवसरजैसी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगातार विफल होता है, तो अराजकतावादी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। यह प्रक्रिया एक आत्म-विनाशकारी दुष्चक्र का निर्माण करती है। राजनीतिकरण समूहों को लामबंद करता है और अक्सर अवास्तविक मांगें पैदा करने लगता है। राज्य इन चौतरफा मांगों के दबाव में आकर लोक-लुभावन घोषणाएं करता है, लेकिन संस्थागत कमजोरी के कारण उन्हें जमीन पर उतारने में नाकाम रहता है। इस नाकामी से जनता में हताशा और आक्रोश तथा विपक्ष का हौसला बढ़ता है। यह आक्रोश आगे चलकर अधिक आक्रामक राजनीतिकरण और नई, कठिन मांगों को जन्म देता है। वर्तमान में व्यवस्था पर दबाव इतना अधिक है कि वह संकट का समाधान करने के बजाय केवल उसे टालने के प्रयास में ही लगी रहती है।

> **अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं की कड़ी समीक्षा होनी चाहिए, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डालती हैं। इसका मतलब हुआ कि राज्य को लोकलुभावनवाद को तिलांजलि देनी होगी और व्यावहारिक तथा टिकाऊ नीतियों की ओर बढ़ना होगा। तभी भारत इस सिस्टम ओवरलोड से उबरकर एक सुदृढ़ और उत्तरदायी महाशक्ति बन सकेगा।**

सौ टके का सवाल यह है कि इन हालात से निकलने का रास्ता क्या है? राजनीतिकरण को कैसे रोका जाए और कैसे संतुलन और संस्थागत सुधार की ओर बढ़ा जाए? इसका रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा। लोकतांत्रिक समाज में चेतना के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता और न ही रोका जाना चाहिए। असली समाधान राजनीतिकरण की ऊर्जा को संस्थागत सुधारों के साथ जोडने से ही संभव है। राज्य की संस्थागत क्षमता का विस्तार ही एकमात्र उपाय है। इसके लिये जबरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है जो अब राजनेताओं में लुप्त होती लगती है क्योंकि सोशल मीडिया के युग में वे सबसे आभासी जुड़ कर भी आम जनता के भौतिक संपर्क से दूर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञ लोग राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक क्षमताओं को दोगुना करने का आसान सा सुझाव देते हैं। मगर इसके लिये गुणवत्ता वाला मानव संसाधन चाहिए जो आता है गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था तथा पारदर्शी और ईमानदार चयन प्रक्रिया से, जिसे राजनीतिकरण ने दूषित और भ्रष्ट कर के रख दिया है। इसके अलावा तकनीकी का उपयोग करके सेवाओं की डिलीवरी को पारदर्शी और त्वरित बनाकर भी राज्य की नाकामी के नैरेटिव को बदला जा सकता है। साथ ही साथ वित्तीय उत्तरदायित्व का भान भी सबको होना जरूरी है। राजनीतिक दलों और जनता के बीच यह स्पष्ट समझ बनानी होगी कि राज्य के संसाधन असीमित नहीं हैं। लोक-लुभावनवाद की योजनाओं की कोई सीमा तय होनी चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों के विकास की कीमत पर तात्कालिक मांगें पूरी न की जाएं। मांगों का लोकतंत्रीकरण और समावेशन भी कम जरूरी नहीं है। सभ्य समाज और समाज के प्रमुखों को ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना पड़ेगा जो विशिष्ट पहचानों के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेहतर सार्वभौमिक अधिकारों पर केंद्रित हो। सबके केंद्र में समान रूप से देश का नागरिक हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय लोकतंत्र मौजूदा समय में एक नाजुक मोड़ पर है। यदि राजनीतिकरण की प्रक्रिया केवल व्यवस्था पर मांगें लादने और उसे पंगु बनाने का जरिया बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब कमजोर व्यवस्था तंत्र के चलते यह विशाल लोकतांत्रिक ढांचा अपने ही बोझ से ढह जाएगा। इसलिए समय की मांग है कि हम मांगों के अधिकार के साथ-साथ व्यवस्था को मजबूत करने के कर्तव्य को भी समझें। राज्य को केवल मांगें पूरी करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक सक्षम, निष्पक्ष और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाली संस्था के रूप में विकसित करें। इस स्थिति से निकलने का एकमात्र तरीका "सख्त वित्तीय अनुशासन" और 'कुशल शासन' ही हो सकता है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं की कड़ी समीक्षा होनी चाहिए, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डालती हैं। इसका मतलब हुआ कि राज्य को लोकलुभावनवाद को तिलांजलि देनी होगी और व्यावहारिक तथा टिकाऊ नीतियों की ओर बढ़ना होगा। तभी भारत इस सिस्टम ओवरलोड से उबरकर एक सुदृढ़ और उत्तरदायी महाशक्ति बन सकेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा देश की जीडीपी को लेकर हम कितना भी इतराते फिरें देशवासियों के जीवन में अच्छे-दिन नहीं आने वाले हैं। बढ़ी हुई जीडीपी से बढ़ी दौलत कुछ लोगों को ही ऊपर उठाती रहेगी।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सदी पुराना एच1एन1 ख़ौफ़ नहीं, सतर्कता ही बचाव

डॉ. मोनिका शर्मा

वर्तमान में फैल रहा स्वाइन फ्लू (एच1एन1) वायरस कोई नया स्ट्रेन नहीं है। इसके लिए मौजूदा टीके तथा दवाइयां पूरी तरह प्रभावी हैं। सतर्कता, मास्क का प्रयोग और सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श ही इस वायरस से बचने का सबसे सटीक हथियार है।

इन दिनों देशभर में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली है, जहां इस साल 3,200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सात वर्षों का रिकॉर्ड है। कोरोना के दौर से गुजर चुके आमजन में इसे लेकर भ्रांतियां और भय बने हुए हैं। चिकित्सा विभाग की भी लगातार सतर्कता बरतने की अपील जारी है। इसके बावजूद कई दशकों का सफर पूरा कर सूअरों से इंसान तक पहुंचा वायरस क्या वाकई अब भी घातक है या सिर्फ मौसमी बीमारी इसकी गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है।

असल में स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होने वाला संक्रामक श्वसन रोग है। साल 1918 में शुरुआत में यह वायरस मुख्य रूप से स्पैनिश फ्लू सूअरों में फैला और उन्हीं के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था, लेकिन बाद में इसी के अंश सूअरों और इंसानों दोनों में अलग रूपों में विकसित हुए, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू नाम दिया गया। हालांकि वक्त के साथ इस वायरस में बदलाव (म्यूटेशन) हुआ और यह इंसानों में भी तेजी से फैलने लगा। इंसानों में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मैक्सिको और अमेरिका में सामने आया। जून, 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को पहली वैश्विक महामारी घोषित किया और अगस्त, 2010 में महामारी खत्म होने की घोषणा हुई। तब से अब तक स्वाइन फ्लू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सीजनल फ्लू का हिस्सा बन चुका है। इसके चलते हर साल मौसम बदलने पर इसके मामले सामने आते हैं।

हाल ही में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के मामलों में भारी उछाल आया है, जो पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक है। राजस्थान में भी कुछ केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह बीमारी आम लोगों के लिए घातक नहीं है, बशर्ते लापरवाही ना बरती जाए और सही समय पर इलाज मिल जाए। चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि यह वायरस तेजी से फैल रहा है और इस बार संक्रमण के मामले पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की हैं और राज्यों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी के मुख्य रूप से दो कारण हैं, मौसम और नमी। मानसून और सर्दियों की शुरुआत के दौरान हवा में अत्यधिक नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव वायरस के पनपने और फैलने के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाते हैं। दूसरा है वायरस में म्यूटेशन यानी स्वरूप बदलना।

एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया के अनुसार, एच1एन1 वायरस समय के साथ अपने स्वरूप (म्यूटेशन) में थोड़ा बदलाव करता रहता है। इस वजह से यह लोगों की मौजूदा इम्युनिटी को चकमा देकर उन्हें आसानी से संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आईसीएमआर ने साफ किया है कि देश में कोई नया या पहले से अधिक जानलेवा स्ट्रेन नहीं मिला है।

सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद) के 32,000 से अधिक नागरिकों पर एक व्यापक सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के करीब 54 फीसदी घरों में कम से कम एक व्यक्ति फ्लू या वायरल बुखार जैसी समस्याओं से पीड़ित पाया गया। 39 प्रतिशत घरों में दो या उससे अधिक लोग एक साथ बीमार थे। लगभग 23 फीसदी घर ऐसे मिले, जहां परिवार के चार या उससे अधिक सदस्य एक साथ फ्लू के लक्षणों से जूझ रहे थे। सर्वे साफ करता है कि भले ही हर मामला स्वाइन फ्लू का न हो, लेकिन इस समय श्वसन संबंधी वायरल संक्रमण बहुत तेजी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है।

वहीं चिकित्सकों का कहना है कि आमजन के लिए यह बीमारी घातक नहीं है। स्वाइन फ्लू के अधिकांश मरीजों में यह वायरस एक सामान्य सर्दी-जुकाम या गंभीर फ्लू की तरह ही व्यवहार करता है, जो उचित आराम और 5-7 दिनों की दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो जाता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह संक्रमण कुछ विशेष श्रेणी के लोगों में गंभीर रूप ले सकता है, जिन्हें चिकित्सा की भाषा में को-मॉर्बिडिटी मरीज कहा जाता है।

जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग (जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है), गर्भवती महिलाएं, पहले से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज, किडनी या दिल की बीमारी से पीड़ित लोग। इन हाई-रिस्क वाले मरीजों में स्वाइन फ्लू बिगड़ने पर निमोनिया या सांस लेने में गंभीर तकलीफ जैसी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो सही समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकती हैं।

अत: इस वायरस संक्रमण से बचाव और सावधानी जरूरी है। यदि आपको तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, अत्यधिक थकान या उल्टी-दस्त जैसी शिकायतें हैं, तो इन्हें सामान्य वायरल न समझें और डॉक्टर से परामर्श लें। बचाव और सावधानी के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकें। समय-समय पर साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें, ताकि घर के अन्य लोग सुरक्षित रहें। डॉक्टरों की सलाह पर सालाना इन्फ्लूएंजा वैक्सीन जरूर लगवाएं, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे। अगर बुखार तीन दिन से ज्यादा रहे, पल्स ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन का स्तर गिरे या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत अस्पताल जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू का प्रकोप व्यापक जरूर है, लेकिन यह नियंत्रित है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा देशभर में लगातार सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण और इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान के लिए देशभर की प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में सैंपलिंग बढ़ाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, वर्तमान में फैल रहा एच1एन1 वायरस कोई नया स्ट्रेन नहीं है। इसके लिए मौजूदा टीके तथा दवाइयां पूरी तरह प्रभावी हैं। सतर्कता, मास्क का प्रयोग और सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श ही इस वायरस से बचने का सबसे सटीक हथियार है। हाई रिस्क वाले मरीजों को विशेष सावधानी बरतने के साथ चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। इस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है।

–डॉ. मोनिका शर्मा,
वरिष्ठ पत्रकार

खारिया खंगार से चूना पत्थर का नया रेल यातायात शुरू हुआ

जोधपुर, (कासं)। माल यातायात बढ़ाने की दिशा में जोधपुर मंडल को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। खारिया खंगार स्टेशन से मंगलम सीमेंट लिमिटेड, कोटा के लिए चूना पत्थर के नए रेल यातायात की शुरुआत हुई है। 21 सितंबर की रात पहली मालगाड़ी की लोडिंग शुरू की गई। खारिया खंगार से कोटा तक 539 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली प्रत्येक रेक से रेलवे को करीब 41.35 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है।

उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंडल में नए माल यातायात को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खारिया खंगार से चूना पत्थर के नए यातायात की शुरुआत इसी प्रयास का परिणाम है। इससे मंडल के माल परिवहन के साथ राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार चालू माह में दो और रेक की लोडिंग प्रस्तावित है।

> **■ जोधपुर मंडल की बड़ी उपलब्धि, रेलवे को करीब 4.13 करोड़ रुपए मिलेंगे**

इसके बाद हर माह 8 से 10 रेक लोड किए जाने का अनुमान है। इस नियमित यातायात से रेलवे को करीब 4.13 करोड़ रुपए की मासिक आय मिलने की संभावना है। खारिया खंगार से शुरू हुआ यह नया यातायात मंडल के माल परिवहन में महत्वपूर्ण जुड़ाव है। चूना पत्थर जैसी बड़ी मात्रा में ढोई जाने वाली सामग्री के रेल परिवहन से रेलवे को नियमित माल यातायात मिलने की उम्मीद है। वहीं मंगलम सीमेंट को लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में कच्चा माल रेल मार्ग से मंगाने की सुविधा मिलेगी।

सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार मंडल प्रशासन की ओर से नए माल ग्राहकों को रेल परिवहन से जोड़ने और मौजूदा माल यातायात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खारिया खंगार से शुरू हुआ चूना पत्थर का यह यातायात इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आने वाले समय में मंडल के माल राजस्व को और बढ़ावा मिलने की संभावना है जिससे मंडल भारतीय रेलवे की आय में और वृद्धि होगी।

अजमेर-उदयपुर रेलखंड पर टिकट जांच अभियान चलाया

अजमेर, (निसं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ जांच अभियान जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव के निर्देशन में अजमेर-उदयपुर-अजमेर रेलखंड पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया।

अभियान का संचालन मंडल वाणिज्य टिकट निरीक्षक केके मौर्य के नेतृत्व में 22 वाणिज्य एवं टिकट जांच कर्मियों की टीम ने किया। टीम ने रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों और संबंधित रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के टिकटों की जांच की। जांच के दौरानबिना टिकट यात्रा करने वाले 259 यात्री पकड़े गए। इनसे 50,995 रुपए किराया और 1,29,500 रुपए अतिरिक्त प्रभार के रूप में वसूल किए गए। इस तरह कुल 1,80,495 रुपए की वसूली हुई। वहीं,उचित श्रेणी का टिकट नहीं होने पर यात्रा करने के 26 मामले सामने आए। इन यात्रियों से 5,170 रुपए किराया और 13,000 रुपए अतिरिक्त प्रभार सहित कुल 18,170 रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा बिना बुक कराए सामान ले जाने के तीन मामलों में 200 रुपए जुर्माना वसूला गया। पूरे अभियान के दौरान कुल288 मामले दर्ज किए गए और यात्रियों से किराये एवं जुर्माने के रूप में 1,98,865 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा उचित और वैध रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें। साथ ही यात्रा के दौरान ले जाए जाने वाले सामान की नियमानुसार बुकिंग करवाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।

पाटन के ग्राम नरसिंहपुरी क्षेत्र में मनरेगा कार्य शुरू करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन

जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पूरे करवाने तथा पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान कराने की मांग की

पाटन, (निसं)। ग्राम पंचायत नरसिंहपुरी क्षेत्र में मनरेगा कार्य तत्काल शुरू करवाने, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पूरे करवाने तथा पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में मंगलवार को ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नौजवानों एवं ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई।

धरने को संबोधित करते हुए जिला सचिव एवं पूर्व सरपंच एडवोकेट कॉमरेड गोपाल सैनी ने कहा कि ग्राम पंचायत नरसिंहपुरी के नरसिंहपुरी, करणपुरा, तिवाड़ी का बास, हुल्डा का बास, झांकड़ा सहित कई गांव-ढाणियों में मनरेगा कार्य बंद पड़े हैं। इससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई स्थानों पर पाइप लाइन के कार्य अधूरे हैं, कहीं पाइप लाइन लीकेज की समस्या है तो कहीं पाइप लाइन डालने के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। गोपाल सैनी ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना है, केवल पाइप लाइन डालना नहीं। उन्होंने प्रशासन से अधूरे कार्यों की मौके पर जांच करवाकर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा कराने, लीकेज पाइप लाइनों को दुरुस्त करने तथा खराब ट्यूबवेलों की मरम्मत करवाकर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। धरने को जिला सचिव कॉमरेड विक्रम यादव एवं किसान सभा जिला अध्यक्ष कॉमरेड ओमप्रकाश सैनी ने भी संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीणों को रोजगार और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की। धरना समाप्त होने के बाद प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मनरेगा कार्य तत्काल शुरू करवाने, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पूरे कराने, लीकेज पाइप लाइनों की मरम्मत, सभी घरों तक पाइप लाइन पहुंचाने तथा खराब ट्यूबवेलों को दुरुस्त करवाने सहित कुल 26 मांगें रखी गईं। प्रशासक ने ग्रामीणों को एक सप्ताह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक करते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरने में कॉमरेड गोपाल सैनी, कॉमरेड विक्रम यादव, कॉमरेड ओमप्रकाश सैनी, जितेंद्र यादव, मुकेश सैनी, श्यामलाल सैनी, धर्मपाल सैनी पंच, सोहनलाल सैनी, मोतीराम सैनी, राहुल सैनी, नंदा बाबा, गोकुल सैनी, पप्पूराम सैनी, छगन लाल सैनी, सुरेश सैनी, सचिन सैनी सहित बड़ी संख्या में नौजवान एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 23 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत-2083, श्रवण नक्षत्र प्रात: 9:09 तक, सुकर्मा योग सायं 4:27 तक, बव करण प्रात: 10:17 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:57 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 9:09 से रात्रि 10:51 तक है। आज श्री वामन जयन्ती, विजया महाद्वादशी व्रत, भुवनेश्वरी जयन्ती, वन बघड़ी, श्रवण द्वादशी व्रत है। पंचक रात्रि 9:57 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया– लाभ अमृत सूर्योदय से 9:19 तक, शुभ 10:49 से रात्रि 12:19 तक, चर 3:14 से 4:49 तक, लाभ 4:49 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 12:00 से 1:30 तक, सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:19

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

तुला
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।`

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।